गेहूं की बिक्री के लिए समुचित समय पर समुचित मूल्य के मामले में उत्तर प्रदेश के लिए अलग से कोई विशेष नीति नहीं है । सरकार द्वारा उद्घोषित गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य तथा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में एक समान है । केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम सांविधिक मूल्यों का निर्धारण किए जाने के बाद अधिकांश राज्य सरकारें चीनी कारखानों को गन्ने के लिए आमतौर से न्यूनतम सांविधिक मूल्य से अधिक कीमत अदा करने की सलाह दे रही हैं ।

जहां तक गेहूं का मामला है, सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत अधिप्राप्ति की जा रही है और किसानों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित सभी भण्डारों को सार्वजनिक अधिप्राप्ति एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही हैं । राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोले गये हैं और उन्हें भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य अधिप्राप्ति एजेंसियों को आवंटित कर दिया गया है ताकि खरीद की जा सके ।

उत्तर प्रदेश में भूकम्प से प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए विदेशी सहायता

751. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत वर्ष उत्तराखंड में भूकम्प से पीड़ित किसानों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि आवंटित की थी और उसमें से कितनी राशि विस्थापित लोगों के पुनर्वास पर खर्च की गई; और

(ख) उपयुक्त सहायता न मिलने के बारे में कितने लोगों ने केन्द्र सरकार को शिकायत की है, साथ ही उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन**) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Amendments in the Indian Veterinary Council Act 1984

752. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government of Maharashtra have requested the Central Government for some amendments in the Indian Veterinary Council Act 1984 so as to protect the practice by the nongraduate Veterinary practitioners in the State; and

(b) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government have proposed inclusion of a provision under Section 30 (b) of the Indian Veterinary Council Act 1984 to permit persons not holding qualifications prescribed in the schedule to the Act but already registered under any State Law prior to the extension of the Act to that State to render minor veterinary services independently.

Floods in Purulia District of West Bengal

753. SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI :
SHRI SUNIL BASU RAY :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what is the estimated loss of property, crops etc., in the recent floods in Purulia district of West Bengal;

(b) whether any financial assistance has been provided to the State Government on this account; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) As per information received from Government of West Bengal, the details